भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4006
12.08.2026 को उत्तर देने के लिए

कार्यक्रम कार्यान्वयन और एमपीलैड्स सुधार

4006. श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री आशीष दुबेः
श्री दामोदर अग्रवालः
कैप्टन बृजेश चौटाः
श्री जशुभाई भिलुभाई राठवाः
श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
श्रीमती बिजुली कलिता मेधीः
श्री मनीष जायसवालः
श्री अभिमन्यु सेठीः
श्रीमती डी. के. अरुणाः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले एक वर्ष में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) को कार्यान्वित करने में किए गए बड़े सुधारों का ब्यौरा क्या है और निधि प्रवाह और डिजिटल निगरानी प्रणाली में सुधार क्या हैं;

(ख) एमपीलैड्स के कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और निगरानी में सुधार करने के लिए ई-साक्षी पोर्टल और अन्य डिजिटल पहलों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) मंत्रालय द्वारा अवसंरचना और परियोजना निगरानी डिवीजन (आईपीएमडी) के माध्यम से बड़े केंद्रीय क्षेत्र अवसंरचना परियोजनाओं को समय पर कार्यान्वित करने की निगरानी के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पूरे देश में परियोजना कार्यान्वयन, वित्तीय पारदर्शिता और विकास परियोजनाओं के समय पर पूरा होने पर इन पहलों का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) मंत्रालय ने पिछले एक वर्ष के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए कई सुधार किए हैं, जिनमें निधि प्रवाह में सुधार, डिजिटल निगरानी, हितधारकों की भागीदारी और क्षमता निर्माण शामिल हैं। विवरण अनुबंध । में हैं।

(ख) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत निधि प्रवाह और परियोजना निगरानी के लिए एमपीलैड्स ईसाक्षी पोर्टल के संचालन के साथ, जिला स्तर पर वास्तविक बैंक खातों में निधि जमा करने की आवश्यकता को एक त्वरित प्रत्यक्ष भुगतान तंत्र द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत भुगतान मंत्रालय द्वारा सीधे विक्रेताओं को किया जाता है। संबंधित केंद्रीय, राज्य और जिला प्राधिकरण लॉगिन के अंतर्गत उपलब्ध समर्पित निगरानी रिपोर्ट तथा डैशबोर्ड, साथ ही ईसाक्षी पोर्टल के सार्वजनिक डैशबोर्ड पर उपलब्ध विखंडित डेटा, विभिन्न समय अंतरालों में स्वीकृति और पूर्णता के लिए लंबित कार्यों सहित कार्यों की स्थिति और प्रगति पर वास्तविक समय की सूचना प्रदान करते हैं। इसने पर्यवेक्षण को सुदृढ़ किया और विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर निगरानी एवं समीक्षा में सुविधा प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष में क्षेत्रीय- स्तर की कार्यशालाओं और मासिक समीक्षा बैठकों सहित आवधिक समीक्षा तंत्रों के संस्थागतकरण ने सामयिक प्रगति सुनिश्चित करने, कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने तथा योजना कार्यान्वयन की समग्र दक्षता में सुधार करने में मदद की है।

(ग) और (घ) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के अवसंरचना एवं परियोजना निगरानी प्रभाग (आईपीएमडी) को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) द्वारा एमओएसपीआई के पैमाना पोर्टल पर प्रदान की गई सूचना के आधार पर 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली चालू केंद्रीय क्षेत्र परियोजना की निगरानी करने का अधिदेश दिया गया है।

सभी हितधारकों (अवसंरचना संबंधी मंत्रालय/विभाग) को पैमाना पर उपलब्ध डेटा एनालिटिक्स के आधार पर उनकी परियोजना की स्थिति और विलंब के बारे में नियमित रूप से सूचित किया जा रहा है, ताकि वे अपनी ओर से परियोजना निष्पादन के प्रबंधन में आवश्यक हस्तक्षेप कर सकें। इसके अतिरिक्त, साक्ष्य-आधारित मासिक समीक्षा बैठकों और अन्य संचार के माध्यम से हितधारकों के साथ नियमित समन्वय निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, अनुकूलित डैशबोर्ड तक पहुँच प्रदान करने वाले लॉगिन क्रेडेंशियल पहले ही सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ साझा कर दिए गए हैं, जिससे उन्हें परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए पोर्टल तक सीधी पहुँच मिलती है।

*****

अनुबंध ।

{दिनांक 12.08.2026 के लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4006 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध}

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत पिछले एक वर्ष में किए गए प्रमुख सुधार

1. योजना के अंतर्गत निधि प्रवाह प्रक्रिया में संशोधनः वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (डीओई) के निर्देशों के अनुसार, एमपीलैड योजना दिनांक 1 अप्रैल 2025 से मॉडल-2 से मॉडल-1ए (टीएसए हाइब्रिड) में स्थानांतरित हो गई। मॉडल-1ए के अंतर्गत एमपीलैड योजना के पीएमयू-सीएनए ने आरबीआई के साथ एक असाइनमेंट खाता खोला है, जो सीएनए के खाते से जुड़ा हुआ है। इस व्यवस्था के अंतर्गत, दिन के दौरान विक्रेताओं/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत बिलों के आधार पर एक समेकित दैनिक निधि की आवश्यकता एसबीआई द्वारा उत्पन्न की जाती है और अनुमोदन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को भेज दी जाती है। पीएफएमएस पर प्रतिदिन की राशि के अनुमोदन पर, सीएनए खाते को आरबीआई असाइनमेंट खाते से संबंधित निधि प्राप्त होती है, जिसे बाद में इसे सीधे संबंधित विक्रेताओं को स्थानांतरित कर दिया जाता है।

2. समीक्षा बैठकों और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का संस्थागतकरण: मंत्रालय ने योजना कार्यान्वयन की निगरानी करने, एमपीलैड्स कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने और परिचालन संबंधी मुद्दों को समाधान करने के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मासिक समीक्षा बैठकें संस्थागत की गई हैं। इसके अतिरिक्त, एमपीलैड्स ई-साक्षी पोर्टल के उपयोग में हितधारकों की क्षमता को सुदृढ़ करने और योजना कार्यान्वयन की दक्षता में सुधार के लिए नियमित क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।

3. एमपीलैड्स के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों की अनिवार्य जियो-टैगिंग: मई 2026 से पूर्ण किए गए एमपीलैड्स कार्यों की जियो-टैग की गई तस्वीरों को अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे वास्तविक सत्यापन को मजबूती मिली है, पारदर्शिता बढ़ी है, पूर्ण परिसंपत्तियों की निगरानी में सुधार हुआ है और कार्यों के कार्यान्वयन में जवाबदेही बढ़ी है।

4. संशोधित सार्वजनिक डैशबोर्ड: योजना की पहुंच, पारदर्शिता और सार्वजनिक समझ में सुधार के लिए एमपीलैड्स पोर्टल के सार्वजनिक डैशबोर्ड को व्यापक रूप से फिर से डिजाइन किया गया है। निम्नलिखित सुधार शुरू किए गए हैं:

• डैशबोर्ड तक पहुंचने से पहले योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया और विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों को रेखांकित करने वाला एक संक्षिप्त व्याख्यात्मक नोट प्रदर्शित किया गया है।

• डैशबोर्ड अब सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से चालू तथा पूर्ण किए गए कार्यों के लिए निधि-आवंटन, कार्य संस्तुति, स्वीकृति, पूर्ण कार्यों, आपदा से संबंधित सहमति और विक्रेता भुगतान से संबंधित सूचना प्रस्तुत करता है। ये सुधार जनता को कार्यान्वयन प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने और स्पष्ट विलंब या निधि से कम उपयोग से उत्पन्न होने वाली गलत धारणाओं को कम करते हैं।

5. पूर्ण किए गए कार्यों की तस्वीरें अपलोड/पुन: अपलोड करना : माननीय संसद सदस्यों को उनके द्वारा संस्तुत पूर्ण कार्यों की तस्वीरें अपलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन एजेंसियां और जिला प्राधिकरण अब जहां भी आवश्यक हो, पूरे किए गए कार्यों की तस्वीरों को फिर से अपलोड कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि पोर्टल पर पूर्ण परिसंपत्तियों के सटीक और अद्यतित दृश्य रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, जिससे पारदर्शिता में सुधार होता है और गलत सूचना की संभावना कम होती है।

6. केंद्रीय नोडल एजेंसी, राज्य नोडल प्राधिकरणों और जिला प्राधिकरणों के लिए प्रगति निगरानी रिपोर्ट एवं डैशबोर्ड: सीएनए, राज्य नोडल प्राधिकरणों और जिला प्राधिकरणों के ई-साक्षी लेखा में समर्पित प्रगति निगरानी रिपोर्ट तथा निगरानी डैशबोर्ड उपलब्ध कराए गए हैं। ये कार्यों की स्थिति और प्रगति के बारे में वास्तविक समय की सूचना प्रदान करते हैं, जिसमें विभिन्न समय अंतराल पर स्वीकृति और पूरा करने के लिए लंबित कार्य शामिल हैं, जो सामयिक हस्तक्षेप और त्वरित कार्यान्वयन हो सकता है।

7. केंद्र और राज्य सरकार योजनाओं की अधिक संख्या शामिल करके अभिसरण रूपरेखा को सुदृढ़ करना और अभिसरण संबंधी डेटा एकत्र करने के लिए पोर्टल पर एक प्रावधान शुरू करना: एमपीलैड योजना के अंतर्गत किए गए विकासात्मक कार्यों के जमीनी स्तर के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, अभिसरण रूपरेखा को अभिसरण के लिए सोलह (16) अतिरिक्त केंद्रीय सरकारी योजनाओं की पहचान करके विस्तारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, एमपीलैड्स ईसाक्षी पोर्टल में अभिसरण डेटा को कैप्चर करने और पात्र केंद्रीय तथा राज्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण में एमपीलैड्स कार्यों की संस्तुति और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समर्पित प्रावधान शुरू किया गया है। इससे कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय संभव होता है, उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देता है और अनुमेय कार्यों के अभिसरण-आधारित कार्यान्वयन को सुदृढ़ करता है।

8. एमपीलैड्स ई-साक्षी पोर्टल और मोबाइल ऐप में निरंतर सुधार: विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर एमपीलैड्स ई-साक्षी पोर्टल और मोबाइल ऐप में कई अन्य विशेषताएं भी आरंभ की गई हैं या बढ़ाई गई हैं, जिनमें स्थल क्षेत्र में विशेष शब्दों को सक्षम करना, जिला प्राधिकरणों को 'कार्य विवरण' फ़ील्ड प्रदर्शित करना और रिपोर्ट तथा डैशबोर्ड में सुधार करना शामिल है।

*****